



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 383]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 11, 2018/आश्विन 19, 1940

No. 383]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 11, 2018/ASVINA 19, 1940

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 2018

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला न्यायालय एजेंसियों का शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियम, 2018

सं. आई.बी.बी.आई./2018-19/जी.एन./आर.ई.जी.035.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196, धारा 203 और धारा 205 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला न्यायालय एजेंसियों का शासी बोर्ड) विनियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला न्यायालय एजेंसियों का शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियम, 2018 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला न्यायालय एजेंसियों का शासी बोर्ड) विनियम, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (क) को उसके खंड (कक) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित खंड (कक) से पूर्व निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
(क) “बोर्ड” से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 188 के अधीन स्थापित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड अभिप्रेत है;।
- मूल विनियमों के विनियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखे जाएंगे, अर्थात्:—

“5. शासी बोर्ड की संरचना – (1) शासी बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—

- (क) प्रबंध निदेशक;
- (ख) स्वतंत्र निदेशक; और
- (ग) शेयरधारक निदेशक

परन्तु शासी बोर्ड में न्यूनतम सात निदेशक होंगे ।

(2) प्रबंध निदेशक को स्वतंत्र निदेशक या शेयरधारक निदेशक नहीं समझा जाएगा ।

(3) किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के किसी कर्मचारी को उसके शासी बोर्ड में प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा किन्तु ऐसे निदेशक को एक शेयरधारक निदेशक को समझा जाएगा ।

(4) आधे से अधिक निदेशक अपनी नियुक्ति के समय और निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सभी समयों पर भारत में निवासी व्यक्ति होंगे ।

(5) स्वतंत्र निदेशकों की संख्या शेयरधारक निदेशकों की संख्या से कम नहीं होगी:

परन्तु शासी बोर्ड की कोई भी बैठक कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक की उपस्थिति के बिना आयोजित नहीं की जाएगी ।

(6) कोई स्वतंत्र निदेशक ऐसा व्यक्ति होगा—

- (क) जो कि योग्य और ईमानदार व्यक्ति है;
- (ख) जिसके पास वित्त, विधि, प्रबंधन या दिवाला के क्षेत्र में विशेषज्ञता है;
- (ग) जो एक दिवाला व्यावसायिक नहीं है;
- (घ) जो शासी बोर्ड के निदेशकों का नातेदार नहीं है;
- (ङ) जिसका दिवाला व्यावसायिक एजेंसी या उसके किसी निदेशक या उसकी दस प्रतिशत से अधिक शेयर पूंजी धारित करने वाले किसी शेयरधारक के साथ ठीक पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों के दौरान या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई धनीय संबंध नहीं था या रहा है;
- (च) जो दिवाला व्यावसायिक एजेंसी का शेयरधारक नहीं है;
- (छ) जो दिवाला व्यावसायिक एजेंसी की दस प्रतिशत से अधिक शेयर पूंजी धारित करने वाले शेयरधारकों के किसी निदेशक बोर्ड का सदस्य नहीं है ।

(7) स्वतंत्र निदेशक, दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा प्रस्तावित नामों की सूची में से बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा ।

(8) कोई व्यक्ति प्रत्येक तीन वर्ष या उसके भाग की अधिकतम दो कार्यावधियों के लिए या सत्तर वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य कर सकेगा ।

(9) उप-विनियम (8) में निर्दिष्ट दूसरी कार्यावधि शासी निकाय द्वारा प्रथम कार्यावधि के संतोषप्रद कार्य-निष्पादन के पुनर्विलोकन के अध्यक्षीन हो सकेगा ।

(10) किसी स्वतंत्र निदेशक के लिए उसी या एक अन्य दिवाला व्यावसायिक एजेंसी में एक शेयरधारक निदेशक बनने के लिए तीन वर्ष की उपशमन अवधि लागू होगी ।

(11) एक-चौथाई निदेशकों से अधिक दिवाला व्यावसायिक नहीं होंगे ।

(12) निदेशक, किसी स्वतंत्र निदेशक का शासी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चयन करेंगे ।

(13) ऐसा निदेशक, जिसका शासी बोर्ड या उसकी किसी समिति की किसी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किए जाने वाले किसी विषय में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई धनीय या अन्यथा हित है, सुसंगत परिस्थितियों के उसकी जानकारी में आने के यथासंभव शीघ्र ऐसी बैठक में अपने हित की प्रकृति को प्रकट करेगा और ऐसा प्रकटन, यथास्थिति, शासी बोर्ड या समिति की

कार्यवाहियों में अभिलिखित किया जाएगा और वह निदेशक उस विषय की बाबत शासी बोर्ड या समिति के किसी विचार-विमर्श या विनिश्चय में भाग नहीं लेगा।

5क. प्रबंध निदेशक (1) प्रत्येक दिवाला व्यावसायिक एजेंसी, बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अधीन रहते हुए, प्रबंध निदेशक की अर्हता और अनुभव, नियुक्ति की रीति, नियुक्ति के निबंधन और शर्तों और उसके चयन और नियुक्ति से सहबद्ध अन्य प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का इस शर्त के अधीन रहते हुए अवधारण करेगी कि—

(क) किसी व्यक्ति का प्रबंध निदेशक के रूप में चयन, कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्र के सभी संस्करणों में खुले विज्ञापन के माध्यम से किया जाएगा;

(ख) प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करते समय किसी व्यक्ति की आयु पचपन वर्ष से अधिक नहीं होगी, जो कि शासी बोर्ड द्वारा उसके लिए कारण अभिलिखित करने के पश्चात् साठ वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी; और

(ग) कोई व्यक्ति पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात्, प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य नहीं करेगा।

(2) प्रबंध निदेशक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति कम से कम तीन वर्ष और अधिकतम पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए होगी।

(3) कोई व्यक्ति अधिकतम दो कार्यावधियों के लिए प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य कर सकेगा।

(4) किसी व्यक्ति की प्रबंध निदेशक के रूप में दूसरी कार्यावधि के लिए नियुक्ति प्रक्रिया नए सिरे से की जाएगी।

(5) प्रबंध निदेशक की नियुक्ति और उसे संदेय पारिश्रमिक का अनुमोदन शासी बोर्ड द्वारा गठित एक प्रतिकर समिति द्वारा किया जाएगा।

(6) प्रबंध निदेशक की नियुक्ति, नियुक्ति का नवीकरण और उसकी सेवाओं का पर्यवसान बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के अध्वधीन होगा।

(7) प्रबंध निदेशक, शासी बोर्ड या बोर्ड द्वारा जारी किए गए निदेशों, दिशानिर्देशों और अन्य आदेशों या नियमों, संगम अनुच्छेदों, दिवाला व्यावसायिक एजेंसी की उप-विधियों को प्रभावी करने में असफल होने पर या अवचार अथवा पद पर बने रहने की अक्षमता के आधार पर शासी बोर्ड द्वारा बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से सेवा से हटाए जाने या सेवा-समाप्ति के लिए दायी होगा।

(8) बोर्ड, स्वप्रेरणा, से प्रबंध निदेशक को, दिवाला समाधान प्रक्रिया के हितधारकों के हित में या लोक हित में, सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात्, यदि उपयुक्त समझे, हटा सकेगा या उसकी नियुक्ति का पर्यवसान कर सकेगा।

(9) प्रबंध निदेशक, सदस्यता समिति, मानिट्रिंग समिति, शिकायत निवारण समिति और अनुशासनिक समिति का पदेन सदस्य होगा।

5ख. अनुपालन—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला न्यायालय एजेंसियों का शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियम, 2018 के प्रारंभ की तारीख को रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक दिवाला व्यावसायिक एजेंसी, ऐसे प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष के भीतर विनियम 5 और उप-विनियम 5क का अनुपालन करेगी।”।

डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./307/18]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला न्यायालय एजेंसियों का शासी बोर्ड) विनियम, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 421, तारीख 21 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.001, तारीख 21 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें अब तक कोई संशोधन नहीं किया गया है।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2018

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA (MODEL BYE-LAWS AND GOVERNING BOARD OF INSOLVENCY PROFESSIONAL AGENCIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2018

No. IBBI/2018-19/GN/REG35.—In exercise of the powers conferred by sections 196, 203 and 205 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016 namely:—

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016, in regulation 2, in sub-regulation (1), clause (a) shall be renumbered as clause (aa) thereof and before clause (aa) as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely: —

‘(a) “Board” means the Insolvency and Bankruptcy Board of India established under section 188 of the Code;’.

3. In the principal regulations, for regulation 5, the following regulations shall be substituted, namely: —

“5. Composition of the Governing Board. — (1) The Governing Board shall consist of—

- (a) managing director;
- (b) independent directors; and
- (c) shareholder directors:

Provided that the Governing Board shall have minimum seven directors.

(2) The managing director shall not be considered either an independent director or a shareholder director.

(3) Any employee of an insolvency professional agency may be appointed as a director on its Governing Board in addition to the managing director, but such director shall be deemed to be a shareholder director.

(4) More than half of the directors shall be persons resident in India at the time of their appointment, and at all times during their tenure as directors.

(5) The number of independent directors shall not be less than the number of shareholder directors:

Provided that no meeting of the Governing Board shall be held without the presence of at least one independent director.

(6) An independent director shall be an individual—

- (a) who is a person of ability and integrity;
- (b) who has expertise in the field of finance, law, management or insolvency;
- (c) who is not an insolvency professional;
- (d) who is not a relative of the directors of the Governing Board;

- (e) who had or has no pecuniary relationship with the insolvency professional agency, or any of its directors, or any of its shareholders holding more than ten per cent. of its share capital, during the immediately preceding two financial years or during the current financial year;
 - (f) who is not a shareholder of the insolvency professional agency;
 - (g) who is not a member of the Board of Directors of any of the shareholders holding more than ten per cent. of the share capital of the insolvency professional agency.
- (7) An independent director shall be nominated by the Board from amongst the list of names proposed by the insolvency professional agency.
- (8) An individual may serve as an independent director for a maximum of two terms of three years each or part thereof, or up to the age of seventy years, whichever is earlier.
- (9) The second term referred to in sub-regulation (8) may be subject to a satisfactory performance review of the first term by the Governing Board.
- (10) A cooling off period of three years shall be applicable for an independent director to become a shareholder director in the same or another insolvency professional agency.
- (11) Not more than one fourth of the directors shall be insolvency professionals.
- (12) The directors shall elect an independent director as the Chairperson of the Governing Board.
- (13) A director, who has, any interest, direct or indirect, pecuniary or otherwise, in any matter coming up for consideration at a meeting of the Governing Board or any of its Committees, shall as soon as possible after relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest at such meeting and such disclosure shall be recorded in the proceedings of the Governing Board or the Committee, as the case may be, and the director shall not take part in any deliberation or decision of the Governing Board or the Committee with respect to that matter.

5A. Managing director. — (1) An insolvency professional agency shall, subject to the guidelines issued by the Board from time to time, determine the qualification and experience, manner of appointment, terms and conditions of appointment and other procedural formalities associated with the selection and appointment of the managing director, subject to the condition that—

- (a) an individual shall be selected as managing director through an open advertisement in all editions of at least one national daily newspaper;
 - (b) an individual at the time joining as managing director shall not be above the age of fifty-five years, which may be relaxed by the Governing Board up to sixty years, after recording reasons therefor; and
 - (c) an individual shall not serve as managing director after he attains the age of sixty-five years.
- (2) The appointment of an individual as the managing director shall be for a tenure of not less than three years but not exceeding five years.
- (3) An individual may serve as managing director for a maximum of two terms.
- (4) The process of appointment for the second term of an individual as managing director shall be conducted afresh.
- (5) The appointment and remuneration payable to the managing director shall be approved by a compensation committee constituted by the Governing Board.
- (6) The appointment, renewal of appointment and termination of service of the managing director shall be subject to prior approval of the Board.

(7) The managing director shall be liable for removal or termination of services by the Governing Board, with the prior approval of the Board, for failure to give effect to the directions, guidelines and other orders issued by the Governing Board or the Board, or the rules, the articles of association or bye-laws of the insolvency professional agency or on the ground of misconduct or incapacity to continue in office.

(8) The Board may *suo motu* remove or terminate the services of the managing director, if it deems fit, in the interest of stakeholders of the insolvency resolution process or in the public interest, after giving a reasonable opportunity of being heard.

(9) The managing director shall be an *ex-officio* member of Membership Committee, Monitoring Committee, Grievance Redressal Committee and Disciplinary Committee.

5B. Compliance. —Every insolvency professional agency registered as on the date of commencement of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2018, shall comply with regulations 5 and 5A within one year from the date of such commencement.”.

Dr. M. S. SAHOO, Chairperson
[ADVT.-III/4/Exty./307/18]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2016 were published *vide* notification No. IBBI/2016-17/GN/REG001 on 22nd November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 421 dated 21st November, 2016 and these have not been amended so far.